



राष्ट्रीय गतिशील दिव्यांगजन संस्थान  
वार्षिक प्रतिवेदन 2016-17

वर्ष 2016-17 की प्राप्तियाँ तथा भुगतान लेखा

प्राप्तियाँ	रु. पै.	रु. पै.	भुगतान	रु. पै.	रु. पै.
आरंभिक बचत			योजना		
बैंक में नाद	3,26,94,135.10		स्थायी संपत्तियाँ		1,98,282.00
नगद राशि	3,54,507.57	3,30,48,642.67	वातानुकूलित/वाटर कूलर		7,02,017.00
			किताबें/जर्नल्स		21,43,334.00
<b>योजना</b>			अस्पताल औजार एवं उपकरण		8,56,315.00
मंत्रालय से प्राप्त अनुदान		17,01,00,000.00	कम्प्यूटर एवं सामग्रियाँ		2,49,512.00
मुल्धन खाता		762.00	भवन		13,740.00
जमा की गई राशि प्रतिदेय	5,26,333.00		कार्यशाला मशीनरी		2,57,950.00
परीक्षा व्यय (भा.पु.प.)	2,20,250.00		इसेकाट्रकल इंस्टालेशन		1,42,183.00
परीक्षा व्यय	2,06,290.00		कार्यालय उपकरण		20,54,292.00
सैलरी भुगतान	82,267.00		फर्नीचर एवं फिक्चर		
जमा सुरक्षा प्रतिदेय-कर्मचारी	95,000.00		सी.पी.एण्ड ओ पाठ्यक्रम		
जमा सुरक्षा प्रतिदेय - ठेकेदार			भौतिक चिकित्सा मशीनरी		62,117.00
	18,153.00	11,48,293.00			66,79,742.00
स्थायी जमा-अन्य (मोड) खाता	35,00,000.00		काशन राशि प्रतिदेय		75,000.00
शोध एवं विकास (उच्च तकनीकी यंत्र एवं उपयंत्र ईएसआईसी से प्राप्त किया गया)	2,41,899.00	37,41,899.00	निर्माण-उपकर		38,922.00
			विज्ञान एवं तकनीक विभाग द्वारा		100.00
<b>निधि अंतरण</b>			जमा की गई राशि प्रतिदेय		2,50,594.00
जेईई		50,00,000.00	परीक्षा व्यय (प.ब.स्वा.वि.वि.वि.)		1,03,206.00
			परीक्षा व्यय (भा.पु.प.)		67,500.00
बैंक ब्याज	11,86,618.00		आयकर-ठेकेदार		3,78,896.00
स्थायी जमा दर, बैंक ब्याज	46,495.00		आयकर - कर्मचारी		3,14,423.00
किताबों का हास	11,169.20		बकाना देयता		53,44,686.00
पाठ्यक्रम शुल्क/पंजीकरण शुल्क	42,900.00		रोजगार कर		78,560.00
विविध प्राप्तियाँ	5,10,483.00		प्रामर्शक-आयकर		1,61,656.00
विवरणवली का विक्रय	1,800.00	17,99,465.20	सैलरी भुगतान		1,56,14,833.00
			विक्रय कर		1,53,481.00
			जमा सुरक्षा प्रतिदेय - कर्मचारी		35,000.00
			जमा सुरक्षा प्रतिदेय - ठेकेदार		16,54,407.00
					2,42,71,264.00
			संस्थाओं को अग्रिम		5,71,52,627.00
			कर्मचारियों को अग्रिम		31,03,082.00
			भुगतान किया गया व्यय		6,922.00
			<b>निधि का अंतरण</b>		
			एजॉल		90,00,000.00
			देहरादून		15,00,000.00
			जेईई		50,00,054.00
					1,55,00,054.00

पाठ्यक्रम शुल्क/पंजीकरण शुल्क		20,030.00
मुलधन निधि		1,59,617.00
विविध प्राप्ति		17,410.00
<b>राजस्व व्यय</b>		
बायोमेट्रिकल वेस्टेज	1,05,414.00	
समाचार पत्र व्यय	39,126.00	
सैलरी एवं भत्ता	2,42,93,975.00	
भविष्य निधि में कर्मचारियों द्वारा अंशदान	37,380.00	
नयी पेंशन योजना में कर्मचारियों द्वारा अंशदान	3,79,233.00	
शिबिर	75,127.00	
सा.आ.पु.परियोजना	1,22,328.00	
अ.का.प्र.क	83,000.00	
गै.स.सं द्वारा निगरानी पर व्यय	16,366.00	
अ.ज.धटको पर व्यय	49,83,662.00	
अ.ज.जा. धटको पर व्यय	24,80,139.00	
गार्डेनिंग/हार्टिकल्चर अनुरक्षण	4,77,214.00	
परामर्शक को मानदेय	1,90,552.00	
बैठक व्यय	6,94,919.00	
अन्तर्राष्ट्रीय दिव्यांगता दिवस/युवा दिवस	1,93,810.00	
सुरक्षा व्यय	33,91,736.00	
सेमिनार, सम्मेलन एवं कार्यशाला	2,49,863.00	
रांची में राष्ट्रीय सम्मेलन	6,22,778.00	
सफाई एवं श्रम शुल्क	49,65,657.00	
यात्रा व्यय	5,25,971.00	
दीर्घकालीन पाठ्यक्रम	1,55,12,636.50	5,94,40,886.50
<b>क्षे. के व्यय</b>		
देहरादून		14,89,601.00
पूर्वात्तर राज्यों हेतु व्यय	93,16,005.00	93,16,005.00
<b>मरम्मत एवं अनुरक्षण</b>		
कम्प्यूटर लेन/नेटवर्क अनुरक्षण	7,23,230.00	
अपरेशन थियेटर का मरम्मत एवं अनुरक्षण	19,206.00	
अग्नि शमन उपकरण	1,21,830.00	
वाताकुलित एवं वाटर कुलर	2,21,742.00	
भवन/सिविल कार्य	65,97,323.00	
इलेक्ट्रीकल फिटिंग	9,32,487.00	



राष्ट्रीय गतिशील दिव्यांगजन संस्थान  
वार्षिक प्रतिवेदन 2016-17

अस्पताल उपकरण लिफ्ट कार्यालय उपकरण भौतिक चिकित्सा पम्प एवं जनरेटर	1,73,327.00 1,23,265.00 3,29,141.00 55,399.00 27,903.00			93,24,853.00
<b>क्षेत्रीय केन्द्र</b> <b>क्षे.के. आइजॉल</b> वेतन एवं भत्ते विद्युत शुल्क दूरभाष शुल्क संगोष्ठी/सम्मेलन कार्यशाला यात्रा व्यय अल्पकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयकर साफ-सफाई एवं संरक्षण किताबें एवं सप्ताहिकी मरम्मत एवं अनुरक्षण कार्यालय व्यय कर्मों को अग्रिम मुद्रण विविध शुल्क गेस्ट फेक्लटी/डॉक्टर को मानदेय बैंक शुल्क डाक व्यय स्थाई सम्पत्तियां - सीपीओ पाठ्यक्रम-आइजॉल	33,00,919.00 32,587.00 35,543.00 3,91,280.00 2,11,353.00 91,890.00 1,41,748.00 17,380.00 1,450.00 21,454.00 12,190.00 4,76,065.00 31,349.00 28,989.00 40,900.00 2,518.50 1,465.00			48,39,080.50 2,77,692.00
<b>क्षेत्रीय केन्द्र</b> <b>क्षे. के. देहरादून</b> वेतन एवं भत्ते बोनस बाल शिक्षा भत्ता एलटीसी/एचटीसी व्यय परामर्श शुल्क विज्ञापन बैंक शुल्क कच्चे पदार्थ/उपयोगी कार्यालय व्यय दूरभाष/फैक्स व्यय मुद्रण/स्टेशनरी साफ-सफाई एवं श्रम शुल्क स्थानीय वाहन व्यय चिकित्सा प्रतिपूर्ति मरम्मत अनुरक्षण विविध व्यय जागरूकता शिविर/अल्पकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम पर व्यय यात्रा व्यय इलेक्ट्रीकिसिटी कोर्स व्यय डाक शुल्क	33,470.00 2,550.00 65.00 10,740.00 90,00,000.00	90,46,825.00		
<b>क्षेत्रीय केन्द्र</b> <b>क्षे. के. देहरादून</b> बैंक ब्याज रा.अ.वि.सं. को अन्तरण विविध प्राप्तियाँ भौ.चि. एवं व्य.चि. सेवाओं से प्राप्त आय वाह्य रोगी विभाग के टिकट से आय	29,248.00 15,00,000.00 4,070.00 64,600.00 3,360.00		16,01,278.00	
				13,58,990.93

क्षेत्रीय केन्द्र क्षे.के. - अरुणाचल प्रदेश रा.अ.वि.सं. को अन्तरण विविध प्राप्ति	496620 95	4,96,715.00	कार्यालय व्यय दुरभाष/फैक्स व्यय मुद्रण एवं स्टेशनरी जागरुकता शिविर एवं अल्पकालिक प्रशिक्षण व्यय मरम्मत अनुरक्षण विविध व्यय यात्रा व्यय इलेक्ट्रीसीटी बैंक शुल्क	6223 3882 25330 68850 16668 54068 6700 32364 221.5	2,14,306.50
जि.वि.पु.के.पोर्ट ब्लेयर बैंक ब्याज		2,478.00	अचल संपत्तियाँ सीपीओ पाठ्यक्रम-अरुणाचल प्रदेश		3,21,151.00
जि.वि.पु.के.राँची बैंक ब्याज		1,272.00			
क.अं.प्र. पाठ्यक्रम- राँची बैंक ब्याज		1,655.00			
गैर-योजना केन्द्र सरकार से प्राप्त अनुदान (सा.न्या. एवं अ.मंत्रालय) 2015-16 में अनुदान प्राप्त किया गया	10,35,00,000.00	10,49,00,000.00	गैर-योजना राजस्व व्यय वेतन एवं भत्ते छुट्टी के बदले रुपये हेतु प्रावधान पेंशन हेतु प्रेच्युटी हेतु प्रावधान कर्मचारियों द्वारा नई पेंशन योजना में अंशदान कर्मचारी कल्याण छुट्टी/गृहयात्रा रियायत (एलटीसी/एचडीटीसी) बोनस बाल शिक्षा भत्ता लेखा परीक्षा शुल्क सामाचार पत्र भत्ते टेलीफोन शुल्क कपड़े धोने का शुल्क चिकित्सा प्रतिपूर्ति इलेक्ट्रिक उर्जा शुल्क स्थानीय वाहन शुल्क डाक शुल्क विविध व्यय कर्मचारियों को अग्रिम विविध व्यय मुद्रण, जिल्दसाजी शुल्क स्टेशनरी व्यय न्यायिक कार्य हेतु शुल्क कार्यालय उपकरण का मरम्मत/अनुरक्षण कर्मचारियों द्वारा नई पेंशन योजना में अंशदान	3,38,46,155.00 53,78,109.00 1,49,77,249.00 4701235.00 11,28,585.00 32,410.00 1,31,385.00 10,19,407.00 2,73,282.00 3,86,725.00 11,048.00 1,55,313.00 1,08,018.00 65,22,359.00 49,42,127.00 23,526.00 92,875.00 5,000.00 74,881.00 53,567.00 47,150.00 11,461.00 1,73,304.00 6,095.00 307146.00	
मूलधन राशि समुह वचत लिफ्ट बीमा योजना एचटीसी/एलटीसी अग्रिम कर्मचारियों को अग्रिम भविष्य निधि में कर्मचारियों द्वारा अंशदान नई पेंशन योजना में कर्मचारियों द्वारा अंशदान सुरक्षा जमा प्रतिदेय चिकित्सा प्रतिपूर्ति पेंशन एवं अन्य लाभ बैंक ब्याज इलेक्ट्रिक शुल्क प्राप्त किया गया विविध आय	1400000.00	19,480.00 1,55,890.00 174.00 16,143.00 29,760.00 3,04,584.00 600.00			
निध का अंतरण रोगीजनों से संग्रह छात्र संग्रह	18,45,527.00 1,49,459.00	19,94,986.00 5,23,069.00 1,86,515.00 591.00			
	65,00,000.00 70,00,000.00	1,35,00,000.00			
					7,44,08,412.00



छोटा शल्य चिकित्सा शुल्क	1,01,561.00				
एक्स-रे शुल्क	7,59,816.00				
कृ. अं. प्र. शुल्क	8,59,578.12				
निविदा प्रामियाँ/आय	93,657.00				
अपेशन थेयेटर शुल्क	51,518.00				
जेरेक्स शुल्क	1,959.00				
विविध प्रामियाँ/आय	64,350.00	46,77,294.12			
<b>गैर योजना</b>					
<b>(छात्रों से संग्रह)</b>					
बैंक ब्याज		2,14,631.00			
स्थायी जमादर पर बैंक ब्याज		4,67,432.00			
काशन राशि प्रतिपूर्ति		5,66,500.00			
निधि अंतरण-योजना		50,00,054.00			
स्थायी जमा (मड)		1,00,00,000.00			
योजना में निधि का अंतरण		200.00			
					66,25,800.00
					115.00
					70,00,000.00
					50,00,000.00
					8,64,570.00
शिक्षण शुल्क	31,30,730.00				
छात्रावास शुल्क	21,16,800.00				
पुस्तकालय शुल्क	9,15,430.00				
विलंब शुल्क	22,735.00				
स्वास्थ्य एवं खेल संबंधित शुल्क	5,400.00				
खेल एवं सांस्कृतिक शुल्क	1,66,700.00				
प्रयोगशाला शुल्क	8,87,530.00	72,45,325.00			
<b>एडिप</b>					
भारत सरकार से प्राप्त अनुदान		2,40,00,000.00			
(सा.न्या.एवं अ. मंत्रालय)					
शिविर एवं जागरूकता	8,700.00				
बैंक ब्याज	8,15,236.00				
					2,45,579.00
					2,16,01,659.00
<b>गैर योजना</b>					
<b>(छात्रों से संग्रह)</b>					
स्थायी जमा (मोड खाता)			50,00,000.00		
काशन राशि प्रतिपूर्ति			16,25,800.00		
कर्मचारियों को अग्रिम					
निधि अंतरण-गैर योजना					
निधि अंतरण-योजना					
निधि का अंतरण-वि. एवं त. वि.					
शिक्षण शुल्क			12,000.00		
छात्रावास शुल्क			10,000.00		
पुस्तकालय शुल्क			4,000.00		
विलंब शुल्क			7,360.00		
प्रयोगशाला शुल्क			4,000.00		
खेल एवं सांस्कृतिक शुल्क			600.00		
छात्रवृत्ति देय					
<b>एडिप</b>					
व्यय हेतु बकाया देयता			61,143.00		
बैंक शुल्क			401.75		
कर्मचारियों को अग्रिम			27,000.00		
जागरूकता, शिविर एवं प्रचार व्यय					
कृत्रिम अंगों व प्रत्यंगों की खरीद					
					37,960.00
					28,000.00



राष्ट्रीय गतिशील दिव्यांगजन संस्थान  
वार्षिक प्रतिवेदन 2016-17

संस्थाओं को अग्रिम कर्मचारियों को अग्रिम कृत्रिम अंगों व प्रत्यंगों की खरीद	16,842.00 4,500.00 23,350.00	8,68,628.00	<u>विज्ञान एवं तकनीकी विभाग</u>		2,19,35,782.75
<u>विज्ञान एवं तकनीकी विभाग</u>					
बैंक ब्याज	59,486.00	59,586.00	कर्मचारियों को अग्रिम	83,565.00	
विविध व्यय	100.00	8,64,570.00	भुगतान नहीं किया गया मानदेय	2,000.00	
छात्र संग्रह निधि अंतरण			रोजगारी कर खाता	1,430.00	
			वेतन एवं भत्ते	2,14,257.00	3,01,252.00
<u>सिपडा</u>			<u>सिपडा</u>		
भारत सरकार से प्राप्त अनुदान (सा. न्या. एवं अ. मंत्रालय)		1,71,22,629.00	कच्चे माल की खरीद	16,00,000.00	
मड खाता		75,00,000.00	संस्थाओं को अग्रिम	21,28,629.00	
बैंक ब्याज	1,64,817.00	3,93,464.00	कौशल विकास कार्य	45,17,500.00	
मड पर बैंक ब्याज	2,28,647.00		छात्र मानदेय	84,25,000.00	1,66,71,129.00
कौशल विकास कार्य	22,45,000.00	45,47,500.00			
छात्र मानदेय	23,02,500.00				
			शेष बचत	8,61,59,945.23	
			बैंक में नगद	88,590.57	
			कार्यालय में नगद		8,62,48,535.80
		44,15,92,889.99			44,15,92,889.99

लेखाकार

लेखा अधिकारी

निदेशक (स्थाना.)



नगद एवं बैंक बचत का विवरण

व्यौरा	खाता सं.	2016-17		2015-16	
		बैंक	नकद	बैंक	नकद
<b>क. योजना निधि</b>					
भारतीय स्टेट बैंक योजना	53015297593	1,52,99,759.40	628.39	1,99,86,087.70	45,203.39
यूबीआई डनलप योजना एवं गैर-योजना		-	17,446.79	-	17,446.79
<b>कुल - क</b>		1,52,99,759.40	18,075.18	1,99,86,087.70	62,650.18
<b>ख. गैर-योजना निधि</b>					
भारतीय स्टेट बैंक गैर-योजना	53015297582	2,56,92,474.78	6,804.64	9,10,995.78	31,974.64
भारतीय स्टेट बैंक - (छात्र संग्रह)	53015297571	44,71,797.18	8,387.00	3,14,100.18	2,28,387.00
भारतीय स्टेट बैंक-रोगीजन संग्रह)	53015335675	1,01,54,337.72	22,338.14	15,78,663.42	85.14
भारतीय स्टेट बैंक - (रोगीजन संग्रह)	36518214169	12,418.81	-	-	-
भारतीय स्टेट बैंक - आरसीआई	53015297616	-	-	-	-
<b>कुल - ख</b>		4,03,31,028.49	37,529.78	28,03,759.38	2,60,446.78
<b>ग. क्षेत्रीय केन्द्र/डीडीआरसी (योजना)</b>					
<b>बचत खाता</b>					
अरुणाचल प्रदेश		10.5	476.00		
पंजाब नेशनल बैंक - रांची		32,594.00	-	31,322.00	-
पंजाब नेशनल बैंक - रांची (सीपीओ पाठ्यक्रम)		42,418.00	-	40,763.00	-
पंजाब नेशनल बैंक - देहरादून		5,18,140.72	32,466.61	2,85,116.65	23,203.61
भारतीय स्टेट बैंक - पोर्ट ब्लेयर		51,181.60	-	48,703.60	-
<b>उप कुल</b>		6,44,344.82	32,942.61	4,05,905.25	23,203.61
<b>चालू खाता (योजना)</b>					
भारतीय स्टेट बैंक - आइजॉल		48,35,918.50	43.00	8,97,702.00	8,207.00
<b>कुल - ग</b>		54,80,263.32	32,985.61	13,03,607.25	31,410.61
<b>घ. उद्दीष्ट निधि शेष</b>					
भारतीय स्टेट बैंक-डीएसटी-नया	33714589171	15,45,819.00	-	9,22,915.00	-
भारतीय स्टेट बैंक-सिपडा	35501283592	1,46,40,227.00	-	17,47,763.00	-
भारतीय स्टेट बैंक-एडिप	53015297627	88,62,848.02	-	59,30,002.77	-
<b>कुल - घ</b>		2,50,48,894.02	-	86,00,680.77	-
<b>कुल (क+ख+ग+घ)</b>		8,61,59,945.23	88,590.57	3,26,94,135.10	3,54,507.57
<b>कुल योग (क+ख+ग+घ)</b>		8,61,59,945.23	88,590.57	3,26,94,135.10	3,54,507.57

लेखाकार

लेखा अधिकारी

निदेशक (स्थाना.)





राष्ट्रीय गतिशील दिव्यांगजन संस्थान  
वार्षिक प्रतिवेदन 2016-17

31 मार्च 2017 के जीपीएफ, सीपीएफ खाते से संबंधित विवरण

मूलधन निधि एवं देयता	2016-17		2015-16	
	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)
मूलधन निधि सा.भ.नि	4,07,311.36			
आरंभिक तलशेष	4,07,311.36		2,81,870.05	
समायोजन का जोड़/घटाव	-		300.00	
व्यय पर अधिक आय का जोड़	3,56,503.10	50,808.26	2,82,170.05	4,07,311.36
मूलधन निधि-अ.भ.नि.	31,64,033.55		1,25,141.31	
आरंभिक तलशेष	31,64,033.55		-	
वर्ष के दौरान समायोजन का जोड़/घटाव	4,77,870.00	36,41,903.55	28,67,061.05	
व्यय पर अधिक आय का जोड़	-		2,96,972.50	
मूलधन निधि-नये भुगतान योजना	-		28,351.00	
आरंभिक तलशेष	-		16,24.00	
वर्ष के दौरान समायोजन का जोड़/घटाव	-		29,975.00	
व्यय पर अधिक आय का जोड़	-		29,975.00	
गैर योजना निधि में कम निधि का अंतरण	6,21,60,594.00	3,00,000.00	-	
सामान्य भविष्य निधि का गैर-योजना में अंतरण	59,83,172.00		5,73,81,166.00	
कर्मचारी की देयता			66,70,275.00	
जीपीएफ				6,40,51,441.00
सीपीएफ				
एनपीएस				
कुल		6,81,43,766.00		6,76,22,785.91
		7,21,36,477.81		
संपत्तियाँ	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)
जमा सुरक्षा				
जीपीएफ	5,16,03,008.35		4,78,39,729.90	
सीपीएफ	55,22,835.00	5,71,25,843.35	82,38,478.00	5,60,78,207.90
प्रोद्दत ब्याज जो प्राप्त नहीं किया गया				
जीपीएफ	71,86,719.45		69,94,131.00	
सीपीएफ	13,50,185.00	85,36,904.45	11,48,409.00	81,42,540.00
स्थायी जमा पर टीडीएस				
जीपीएफ	81,162.00	81,213.00		
सीपीएफ	51.00	37,867.00		
जीपीएफ-योजना निधि अंतरण				
वापस योग्य अग्रिम	17,09,020.00	17,60,072.00	14,72,907.00	15,37,909.00
जीपीएफ	51,052.00		65,002.00	
सीपीएफ				
बैंक अंतशेष				
यूबीआई	15,93,625.46		14,81,709.46	
यूबीआई	30,00,952.55	45,94,578.01	3,82,419.55	18,64,129.01
कुल		7,21,36,477.81		6,76,22,785.91

लेखाकार

लेखा अधिकारी

निदेशक (स्थाना.)



वर्ष 2016-17 के आय एवं व्यय के लिए खाते (सा.भ.नि. एद.भ.)

व्यय	2016-2017		2015-2016		2016-2017		2015-2016	
	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)
ब्याज								
जी.पी.एफ.	44,64,369.00		45,44,747.00		40,37,028.90		45,79,444.31	
सी.पी.एफ.	2,94,041.00		5,51,033.00		7,62,765.00		8,28,249.00	
	-	47,58,410.00	-	50,95,780.00	-	47,99,793.90	-	54,07,693.31
बैंक शुल्क								
जी.पी.एफ.	599.00		175.00					
सी.पी.एफ.	108.00	707.00	1.50	176.50	71,436.00		90,619.00	
व्यय के ऊपर अधिक आय					9,254.00		19,758.00	
सा.भ.न.			1,25,141.31			80,690.00	1,624.00	1,12,001.00
अ.द.भि.नि.	4,77,870.00		2,96,972.50					
न.पे.यो.			1,624.00	4,23,737.81		3,56,503.10		
		52,36,987.00		55,19,694.31		52,36,987.00		55,19,694.31

लेखाकार

लेखा अधिकारी

निदेशक (स्थाना.)



वर्ष 2016-17 के आय एवं व्यय के लिए खाते (सा.भ.नि. अ.द.भ.)

प्राप्तियां	राशि (रु.)	राशि (रु.)	भुगतान	राशि (रु.)	राशि (रु.)
<b>आरम्भिक शेष</b>					
आई.डी.बी.आई. बैंक न.पे.यो.	14,81,709.46				
यूबीआई -सा.भ.न.	3,82,419.55	18,64,129.01			
यूबीआई-अं.दा.भ.नि.					
<b>अं.दा.भ.नि. खाता</b>					
प्रतिदेय अग्रिम	4,27,459.00		अं.दा.भ.नि. खाता		
बैंक ब्याज बचत खाता	9,254.00		बैंक शुल्क	108.00	
बैंक ब्याज एफ.डी.आर	1,82,859.00		कर्मचारियों का अंश दान/कर्मचारी	16,14,148.00	
स्थाई जमा	27,16,746.00		निधि का अंतरण सा.भ.न.		16,14,256.00
गैर-योजना में निधि का अंतरण	3,00,000.00		निधि का अंतरण-गैर-योजना		
उपार्जित ब्याज	3,76,976.00				
उपार्जित ब्याज	13,950.00				
कर्मचारी अंशदान पर ब्याज	2,05,545.00	42,32,789.00			
<b>सा.भ.नि. खाता</b>					
प्रतिदेय अग्रिम	6,44,038.00		सा.भ.न. खाता		
बैंक ब्याज बचत खाता	71,436.00		बैंक शुल्क	599.00	
कर्मचारियों द्वारा अंश-दान	81,42,166.00	88,57,640.00	अग्रिम प्रतिदेय	8,80,151.00	
			अंतिम आहरण	78,64,974.00	87,45,724.00
			अंतिम शेष		-
			आई.डी.बी.आई. बैंक-न.पे.यो.		
			यूबीआई-सा.भ.न.	15,93,625.46	
			यूबीआई-अं.दा.भ.नि.	30,00,952.55	45,94,578.01
		1,49,54,558.01			1,49,54,558.01

लेखाकार

लेखा अधिकारी

निदेशक (स्थाना.)

## 31.03.2017 के निवेश का विवरण

क्र. सं.	बैंक का नाम	एफडी सं.	दिनांक	आरम्भ मूल्य	परिपक्वता	अन्तः मूल्य	परिपक्वता का मूल्य	ब्याज दर	पूर्णता का दिनांक	प्रोदभुत ब्याज 31-03-16	वर्ष हेतु ब्याज (2016-17)	उपजित ब्याज मेच्योर हुआ	तत्कालिक वर्ष का ब्याज मेच्योर हुआ	टीडीएस	कुल ब्याज से आय
1	पीएनबी	157500PR00009432	16-10-2014	4,19,862.00	-	4,19,862.00	5,46,361.00	9.00	16-10-2017	58,262.00	44,506.00	1,02,768.00	-	-	44,506.00
2	पीएनबी	157500PR00009399	16-10-2014	50,24,203.00	-	50,24,203.00	66,61,860.00	9.00	16-10-2017	6,97,158.00	5,32,888.00	12,29,726.00	-	-	5,32,888.00
3	पीएनबी	157500PR00009404	17-10-2014	27,16,746.00	-	-	-	-	-	-	5,59,835.00	37,697.00	182,859.00	-	1,82,859.00
4	पीएनबी	157500PR00009309	16-10-2014	72,632.00	-	72,632.00	89,173.00	9.00	05-02-2017	10,078.00	7,421.00	17,499.00	-	-	7,421.00
5	एसबीआई	33856206720	26-05-2014	5,035.00	6,138.00	-	6,189.00	9.00	20-09-2016	5,935.00	-	192.00	852	51.00	(4,781.00)
										82,39,478.00	11,44,522.00	13,50,165.00	1,83,161.00	51.00	7,62,765.00
										55,22,835.00	5,083.00	192.00	-	-	192.00

अं.प्र.नि.

क्र. सं.	बैंक का नाम	एफडी सं.	दिनांक	आरम्भ मूल्य	परिपक्वता	अन्तः मूल्य	परिपक्वता का मूल्य	ब्याज दर	पूर्णता का दिनांक	प्रोदभुत ब्याज 31-03-16	वर्ष हेतु ब्याज (2016-17)	उपजित ब्याज मेच्योर हुआ	तत्कालिक वर्ष का ब्याज मेच्योर हुआ	टीडीएस	कुल ब्याज से आय
1	पीएनबी	157500PR00009441	16-10-2014	4,89,680.00	-	4,89,680.00	6,39,547.00	9.00	16-10-2017	67,947.00	50,943.00	1,18,890.00	-	-	50,943.00
2	पीएनबी	157500PR00009450	16-10-2014	40,96,970.00	-	40,96,970.00	53,50,848.00	9.00	16-10-2017	5,68,465.00	4,29,733.00	9,98,288.00	-	-	4,29,733.00
3	पीएनबी	157500PR00009469	16-10-2014	35,11,250.00	-	35,11,250.00	45,85,868.00	9.00	16-10-2017	4,87,221.00	3,70,813.00	8,58,034.00	-	-	3,70,813.00
4	पीएनबी	157500PR00009423	16-10-2014	65,25,521.00	-	65,25,521.00	85,25,521.00	9.00	16-10-2017	9,05,481.00	6,78,874.00	15,84,355.00	-	-	6,78,874.00
5	पीएनबी	157500PR00009415	16-10-2014	13,54,256.00	-	13,54,256.00	17,68,726.00	9.00	16-10-2017	1,87,916.00	1,40,888.00	3,28,804.00	-	-	1,40,888.00
										1,59,77,677.00	16,71,311.00	38,88,371.00	-	-	16,71,311.00
6	एसबीआई	6302859423	28-12-2014	40,34,415.00	-	40,34,415.00	51,92,367.00	8.50	28-12-2017	4,50,931.00	78,725.00	5,29,656.00	-	-	78,725.00
7	एसबीआई	3168587504	25-12-2013	44,74,770.42	56,86,456.00	-	57,09,813.00	9.00	20-09-2016	10,00,899.00	2,34,144.00	12,35,043.00	-	-	2,34,144.00
8	एसबीआई	31612751466	29-10-2013	72,81,634.00	92,65,702.00	-	69,25,692.00	7.25	17-06-2019	17,53,726.00	2,21,354.00	19,75,080.00	-	-	2,21,354.00
9	एसबीआई	33574534988	09-01-2014	18,44,800.00	23,77,412.00	-	24,09,401.00	9.00	09-01-2017	4,04,401.00	1,60,200.00	5,64,601.00	-	-	1,60,200.00
10	एसबीआई	33856208149	26-05-2014	20,700.00	25,340.00	-	25,445.00	9.00	20-09-2016	3,703.00	1,042.00	4,745.00	-	-	1,042.00
11	एसबीआई	33856205921	26-05-2014	11,170.00	13,506.00	-	13,544.00	9.00	25-07-2016	1,998.00	992.00	2,990.00	-	-	992.00
										4,38,52,563.00	705.00	4,39,230.00	-	-	705.00
										1,76,67,489.42	9,80,569.00	12,71,300.00	6,51,777.00	81,162.00	14,72,146.00
12	यूबीआई	0735233 [0071102374568]	31-03-2015	50,72,788.99	-	50,72,788.99	64,80,988.08	8.25	31-03-2018	4,33,785.00	4,68,465.37	(1,16,621.03)	7,85,633.34	-	3,51,944.34
13	यूबीआई	990313 [0071102394541]	04-12-2014	20,46,747.98	-	20,46,747.98	26,34,202.78	8.50	04-12-2017	2,41,473.00	2,00,785.09	(49,603.68)	3,92,654.41	-	1,51,181.41
14	यूबीआई	990314 [0071102394500]	04-12-2014	20,46,751.78	-	20,46,751.78	26,34,307.68	8.50	04-12-2017	2,41,473.00	2,00,785.46	(1,21,804.23)	3,20,454.23	-	78,981.23
15	यूबीआई	990315 [0071102394550]	04-12-2014	20,46,319.42	-	20,46,319.42	26,33,651.22	8.50	04-12-2017	2,41,425.00	2,00,743.00	(49,594.19)	3,92,571.81	-	1,51,148.81
16	यूबीआई	0855763 [0071102321507]	20-03-2013	29,81,955.31	29,81,955.31	-	30,09,891.76	-	30-06-2016	3,255.00	24,681.45	3,255.00	-	-	24,681.45
										1,41,94,563.48	12,31,950.03	20,27,048.45	-	-	8,93,571.90
										1,42,22,499.93	3,37,623.13	3,37,623.13	-	-	3,37,623.13
										4,78,39,729.90	38,83,075.03	71,86,719.45	6,51,777.00	81,162.00	40,37,028.90

कुल योग

रोगी संग्रह से प्राप्त का निवेश

क्र. सं.	बैंक का नाम	एफडी सं.	दिनांक	आरम्भ मूल्य	परिपक्वता	अन्तः मूल्य	परिपक्वता का मूल्य	ब्याज दर	पूर्णता का दिनांक	प्रोदभुत ब्याज 31-03-16	वर्ष हेतु ब्याज (2016-17)	उपजित ब्याज मेच्योर हुआ	तत्कालिक वर्ष का ब्याज मेच्योर हुआ	टीडीएस	कुल ब्याज से आय
1	एसबीआई	6304686656	28-12-2014	62,51,151.00	-	62,51,151.00	80,45,348.00	8.50	28-12-2017	6,88,696.00	6,09,900.00	13,08,596.00	-	-	-
2	एसबीआई	6304598479	31-03-2016	18,90,153.00	-	18,90,153.00	24,32,662.00	8.50	31-03-2018	1,66,209.00	1,80,463.00	3,46,672.00	-	-	-
3	एसबीआई	63020201170	16-01-2016	25,50,135.00	-	25,50,135.00	32,82,071.00	8.50	16-01-2018	2,72,704.00	2,47,607.00	5,20,311.00	-	-	-
4	एसबीआई	63029438965	28-12-2014	21,58,529.00	-	21,58,529.00	27,18,667.00	8.50	28-12-2017	2,41,260.00	2,10,599.00	4,51,859.00	-	-	-
5	एसबीआई	63029282371	16-01-2016	20,67,887.00	-	20,67,887.00	26,61,409.00	8.50	16-01-2018	2,21,133.00	2,00,783.00	4,21,916.00	-	-	-
										1,49,17,855.00	14,48,342.00	30,49,344.00	-	-	-

लेखाकार

लेखा अधिकारी

निदेशक (स्थाना.)





31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष का आय और व्यय का अनुसूचित लेखा भाग

सूची-24 सार्थ लेखा-नीति

1. कर्मचारी से संबंधित व्यय का लेखा नकद आधार पर किया जाता है।
2. मंत्रालय से अनुमोदन के शर्तों पर कार्पस निधि के सृजन के लिए एक बैंक खाता खोला गया है जिसमें समस्त विभागीय प्राप्तियां तथा बैंक द्वारा अर्जित ब्याज को सेवा निवृत्ति हितलाभ हेतु जमा किया जा रहा है। जबकि वर्तमान में सेवा निवृत्ति हितलाभ नकद आधार पर गैर-योजना से ज्यादा किया जा रहा है।
3. 1961 आयकर अधिनियम में लिखित दर तथा प्रदान किये गये दर के आधार पर स्थायी परिसम्पति का मूल्यह्रास हो गया है।

लेखाकार

लेखा अधिकारी

निदेशक (स्थाना.)

### 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष का आय और व्यय का अनुसूचित लेखा भाग

#### अनुसूची - 25 आकस्मिक देनदारी तथा लेखा पर टिप्पणी

##### क. आकस्मिक देनदारी

1. संस्था के खिलाफ दावा कर्ज के रूप में स्वीकार नहीं - शून्य
2. पार्टी के लिए दायित्व निवेश का भुगतान - शून्य
3. बकाया वायदा विनिमय अनुबन्ध के खातों पर दायित्व - शून्य
4. जागीदार और बकाया ऋण का पत्र - शून्य

##### ख. लेखा पर टिप्पणी:

1. सूची 1-25 को जोड़ने के कारण 31.03.2016 तक का तुलन-पत्र एक समकालीन भाग बना और आय तथा व्यय लेखा समाप्त हुए वर्ष के उसी दिनांक को।
2. शेष संविदाओं का अनुमानित मूल्य मूलधन लेखा पर कार्यान्वित किया गया है न कि दर्शाये गये (अग्रिम का निवल) रु. शून्य (गत वर्ष रु. शून्य)।
3. लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक:

	2016-17	2015-16
<u>लेखा परीक्षकों के अनुसार</u>		
- काराधान संबंधी	-	-
- प्रबंध सेवा हेतु	-	-
- प्रमाण पत्र हेतु	366600.00	335965.00
अन्य (आंतरिक लेखा परीक्षा)	20125.00	45000.00

4. गत वर्ष के आंकड़ों का चालू वर्ष के आंकड़ों से साम्य हेतु जहाँ भी आवश्यक समझा गया उसे पुनः वर्गीत/पुनः विन्यास किया गया।
5. संस्थान का वार्षिक लेखा नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक के किये गये संशोधित विहित प्रपत्र में तैयार किया गया है।
6. उपलब्ध विस्तृत सूचना तथा अभिलेख के अनुसार जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र (डीडीआरसी) क्षेत्र (आरसी) की प्राप्ति एवं भुगतान को वार्षिक लेखा में सम्मिलित किया गया।
7. अवधि के दौरान कर्मियों को दिये गये अग्रिम को उपयुक्त शीर्ष के अधीन रखा गया है। विगत वर्षों के असमायोजित अग्रिमों को उपयुक्त शीर्ष के अधीन रखा गया है। विगत वर्षों के असमायोजित अग्रिमों का समाधान अग्रिम किया गया है।
8. एडिप निधि, कार्पस निधि, संयुक्त प्रवेश परीक्षा संयोजित पुनर्वास केन्द्र निधि संयोजित पुनर्वास केन्द्र निधि डीआर एक निधि डीएसटी निधि तथा भारतीय पुनर्वास परिषद निधि व तैयार नहीं किया गया है। तदनुसार एडिप माल के स्टॉक के मूल्य को निर्दिष्ट सूची में दर्शाया नहीं गया है। एडिप योजना अधीन 31.03.2017 तक पिछले वर्ष का 33.74 +ए16 लाख (गत वर्ष 29.24 लाख)
9. एक्यूरिस्ट द्वारा तैयार किये गये परिकलन के आधार पर संस्थान ने आय और व्यय खाते में उपदान/पेंशन के खाते पर देयता को दर्शाया है। ग्रेच्युटी/पेंशन के खाते पर व्यय हेतु मंत्रालय से प्राप्त सहायता अनुदान राशि के द्वारा भुगतान किया गया।



## राष्ट्रीय गतिशील दिव्यांगजन संस्थान वार्षिक प्रतिवेदन 2016-17

10. वर्ष के दौरान क्रय किये गये प्रयोगशाला भण्डार, लघु अनुषंगियां, सामग्रियों, लेखन सामग्री, दवाओं इत्यादि के मूल्य को आय तथा व्यय लेखा में दो।
11. भविष्य निधि नियमों की धारा 8(2) के अधीन भारत राज-पत्र में अधिसूचना जारी करने के विषय को संस्थान ने सामाजिक न्याय और अधिकारी अवगत किया। भारत सरकार के राज-पत्र में अधिसूची जारी न करने के फलस्वरूप सा.भ.नि./अं.भ.नि. के अधीन संचित निधियों को अनुसूचित बैंकों को सावधान किया गया है।
12. आर.के लोढ़ा एवं एसोसिएट्स ने भौतिक अचल संपत्तियों का सत्यापन और बही-खातों के साथ अपने सुलह बाहर ले जाने के लिए लगे हुए किया गया है। इससे पहले कोई भी तुलनात्मक भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन नहीं बनाया गया। प्रतिवेदन के अनुसार उनके द्वारा लेखा में 133.78 लाख (कुल मूल्य) कमी/मूल्य ह्रास को प्रतिवेदन में चिन्हित किया गया है जो 5 प्रतिशत से कम है। अस्थायी संपत्तियों का ह्रास हो चुका है। एक भाग से बहुत सारे ऐसे पदार्थों के साथ अचल संपत्तियों को प्रकृति के अनुसार उपभोग्य की तरह है जैसे लकड़ी का कार्या कमी/मूल्य ह्रास की सूची जो संबंधित विभागों में दिया गया जैसे कैमरा, प्रोजेक्टर, साह जो उन्हें दिखाया गया, उनके द्वारा नवीन प्रतिवेदन उनके अनुशंसा पर तैयार करने हेतु जमा किया गया। अंतिम निर्णय प्रबंधन के द्वारा नवीन प्रतिवेदन प्राप्त करने के उपरांत दिया जाएगा एवं आवश्यक समायोजन बनाने एवं क्रमशः लेखा किताब को पारदर्शी बनाने के लिए किया गया।
13. वर्ष के दौरान 1514178.00/- (पिछले साल 3591054.00 की राशि) चालू वर्ष के दौरान अतिरिक्त मूल्य पर अवमूल्यन की उसी राशि को एएस-12 राशि के रूप में जमा की गई। - अचल संपत्तियों के मूल्य को कम कर दिखाया गया है। - सरकार से अनुदान सहायता प्रोद्भवन आधार पर की जा रही है।

लेखाकार

लेखा अधिकारी

निदेशक (स्थाना.)

# **अध्याय-X**

**दिव्यांगजन अधिनियम, 2016**





सत्यमेव जयते

# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II — खण्ड 1

PART II — Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 59] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 28, 2016/ पौष 07, 1938 (शक)  
No. 59] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 28, 2016/ PAUSHA 07, 1938 (SAKA)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

## MINISTRY OF LAW AND JUSTICE (Legislative Department)

*New Delhi, the 28th December, 2016/Pausha 17, 1938 (Saka)*

The following Act of Parliament received the assent of the President on the 27th December, 2016, and is hereby published for general information:—

### THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES ACT, 2016

(No. 49 OF 2016)

[27th December, 2016]

An Act to give effect to the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities and for matters connected therewith or incidental thereto.

WHEREAS the United Nations General Assembly adopted its Convention on the Rights of Persons with Disabilities on the 13th day of December, 2006;

AND WHEREAS the aforesaid Convention lays down the following principles for empowerment of persons with disabilities,—

- (a) respect for inherent dignity, individual autonomy including the freedom to make one's own choices, and independence of persons;
- (b) non-discrimination;
- (c) full and effective participation and inclusion in society;
- (d) respect for difference and acceptance of persons with disabilities as part of human diversity and humanity;

(e) equality of opportunity;

(f) accessibility;

(g) equality between men and women;

(h) respect for the evolving capacities of children with disabilities and respect for the right of children with disabilities to preserve their identities;

AND WHEREAS India is a signatory to the said Convention;

AND WHEREAS India ratified the said Convention on the 1st day of October, 2007;

AND WHEREAS it is considered necessary to implement the Convention aforesaid.

BE it enacted by Parliament in the Sixty-seventh Year of the Republic of India as follows:—

## CHAPTER I

### PRELIMINARY

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016.

(2) It shall come into force on such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

Definitions.

2. In this Act, unless the context otherwise requires,—

(a) “appellate authority” means an authority notified under sub-section (3) of section 14 or sub-section (1) of section 53 or designated under sub-section (1) of section 59, as the case may be;

(b) “appropriate Government” means,—

(i) in relation to the Central Government or any establishment wholly or substantially financed by that Government, or a Cantonment Board constituted under the Cantonments Act, 2006, the Central Government;

(ii) in relation to a State Government or any establishment, wholly or substantially financed by that Government, or any local authority, other than a Cantonment Board, the State Government.

(c) “barrier” means any factor including communicational, cultural, economic, environmental, institutional, political, social, attitudinal or structural factors which hampers the full and effective participation of persons with disabilities in society;

(d) “care-giver” means any person including parents and other family Members who with or without payment provides care, support or assistance to a person with disability;

(e) “certifying authority” means an authority designated under sub-section (1) of section 57;

(f) “communication” includes means and formats of communication, languages, display of text, Braille, tactile communication, signs, large print, accessible multimedia, written, audio, video, visual displays, sign language, plain-language, human-reader, augmentative and alternative modes and accessible information and communication technology;

(g) “competent authority” means an authority appointed under section 49;

(h) “discrimination” in relation to disability, means any distinction, exclusion, restriction on the basis of disability which is the purpose or effect of impairing or nullifying the recognition, enjoyment or exercise on an equal basis with others of all human rights and fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural, civil or any other field and includes all forms of discrimination and denial of reasonable accommodation;



18 of 2013.

(i) "establishment" includes a Government establishment and private establishment;

(j) "Fund" means the National Fund constituted under section 86;

(k) "Government establishment" means a corporation established by or under a Central Act or State Act or an authority or a body owned or controlled or aided by the Government or a local authority or a Government company as defined in section 2 of the Companies Act, 2013 and includes a Department of the Government;

(l) "high support" means an intensive support, physical, psychological and otherwise, which may be required by a person with benchmark disability for daily activities, to take independent and informed decision to access facilities and participating in all areas of life including education, employment, family and community life and treatment and therapy;

(m) "inclusive education" means a system of education wherein students with and without disability learn together and the system of teaching and learning is suitably adapted to meet the learning needs of different types of students with disabilities;

(n) "information and communication technology" includes all services and innovations relating to information and communication, including telecom services, web based services, electronic and print services, digital and virtual services;

(o) "institution" means an institution for the reception, care, protection, education, training, rehabilitation and any other activities for persons with disabilities;

41 of 2006.

(p) "local authority" means a Municipality or a Panchayat, as defined in clause (e) and clause (f) of article 243P of the Constitution; a Cantonment Board constituted under the Cantonments Act, 2006; and any other authority established under an Act of Parliament or a State Legislature to administer the civic affairs;

(q) "notification" means a notification published in the Official Gazette and the expression "notify" or "notified" shall be construed accordingly;

(r) "person with benchmark disability" means a person with not less than forty per cent. of a specified disability where specified disability has not been defined in measurable terms and includes a person with disability where specified disability has been defined in measurable terms, as certified by the certifying authority;

(s) "person with disability" means a person with long term physical, mental, intellectual or sensory impairment which, in interaction with barriers, hinders his full and effective participation in society equally with others;

(t) "person with disability having high support needs" means a person with benchmark disability certified under clause (a) of sub-section (2) of section 58 who needs high support;

(u) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;

(v) "private establishment" means a company, firm, cooperative or other society, associations, trust, agency, institution, organisation, union, factory or such other establishment as the appropriate Government may, by notification, specify;

(w) "public building" means a Government or private building, used or accessed by the public at large, including a building used for educational or vocational purposes, workplace, commercial activities, public utilities, religious, cultural, leisure or recreational activities, medical or health services, law enforcement agencies, reformatories or judicial foras, railway stations or platforms, roadways bus stands or terminus, airports or waterways;

(x) "public facilities and services" includes all forms of delivery of services to the public at large, including housing, educational and vocational trainings, employment



and career advancement, shopping or marketing, religious, cultural, leisure or recreational, medical, health and rehabilitation, banking, finance and insurance, communication, postal and information, access to justice, public utilities, transportation;

(y) “reasonable accommodation” means necessary and appropriate modification and adjustments, without imposing a disproportionate or undue burden in a particular case, to ensure to persons with disabilities the enjoyment or exercise of rights equally with others;

(z) “registered organisation” means an association of persons with disabilities or a disabled person organisation, association of parents of persons with disabilities, association of persons with disabilities and family members, or a voluntary or non-governmental or charitable organisation or trust, society, or non-profit company working for the welfare of the persons with disabilities, duly registered under an Act of Parliament or a State Legislature;

(za) “rehabilitation” refers to a process aimed at enabling persons with disabilities to attain and maintain optimal, physical, sensory, intellectual, psychological environmental or social function levels;

(zb) “Special Employment Exchange” means any office or place established and maintained by the Government for the collection and furnishing of information, either by keeping of registers or otherwise, regarding—

(i) persons who seek to engage employees from amongst the persons with disabilities;

(ii) persons with benchmark disability who seek employment;

(iii) vacancies to which persons with benchmark disabilities seeking employment may be appointed;

(zc) “specified disability” means the disabilities as specified in the Schedule;

(zd) “transportation systems” includes road transport, rail transport, air transport, water transport, para transit systems for the last mile connectivity, road and street infrastructure, etc.;

(ze) “universal design” means the design of products, environments, programmes and services to be usable by all people to the greatest extent possible, without the need for adaptation or specialised design and shall apply to assistive devices including advanced technologies for particular group of persons with disabilities.

## CHAPTER II

### RIGHTS AND ENTITLEMENTS

Equality and non-discrimination.

3. (1) The appropriate Government shall ensure that the persons with disabilities enjoy the right to equality, life with dignity and respect for his or her integrity equally with others.

(2) The appropriate Government shall take steps to utilise the capacity of persons with disabilities by providing appropriate environment.

(3) No person with disability shall be discriminated on the ground of disability, unless it is shown that the impugned act or omission is a proportionate means of achieving a legitimate aim.

(4) No person shall be deprived of his or her personal liberty only on the ground of disability.

(5) The appropriate Government shall take necessary steps to ensure reasonable accommodation for persons with disabilities.



4. (1) The appropriate Government and the local authorities shall take measures to ensure that the women and children with disabilities enjoy their rights equally with others.

Women and children with disabilities.

(2) The appropriate Government and local authorities shall ensure that all children with disabilities shall have right on an equal basis to freely express their views on all matters affecting them and provide them appropriate support keeping in view their age and disability.”.

5. (1) The persons with disabilities shall have the right to live in the community.

Community life.

(2) The appropriate Government shall endeavour that the persons with disabilities are,—

(a) not obliged to live in any particular living arrangement; and

(b) given access to a range of in-house, residential and other community support services, including personal assistance necessary to support living with due regard to age and gender.

6. (1) The appropriate Government shall take measures to protect persons with disabilities from being subjected to torture, cruel, inhuman or degrading treatment.

Protection from cruelty and inhuman treatment.

(2) No person with disability shall be a subject of any research without,—

(i) his or her free and informed consent obtained through accessible modes, means and formats of communication; and

(ii) prior permission of a Committee for Research on Disability constituted in the prescribed manner for the purpose by the appropriate Government in which not less than half of the Members shall themselves be either persons with disabilities or Members of the registered organisation as defined under clause (z) of section 2.

7. (1) The appropriate Government shall take measures to protect persons with disabilities from all forms of abuse, violence and exploitation and to prevent the same, shall—

Protection from abuse, violence and exploitation.

(a) take cognizance of incidents of abuse, violence and exploitation and provide legal remedies available against such incidents;

(b) take steps for avoiding such incidents and prescribe the procedure for its reporting;

(c) take steps to rescue, protect and rehabilitate victims of such incidents; and

(d) create awareness and make available information among the public.

(2) Any person or registered organisation who or which has reason to believe that an act of abuse, violence or exploitation has been, or is being, or is likely to be committed against any person with disability, may give information about it to the Executive Magistrate within the local limits of whose jurisdiction such incidents occur.

(3) The Executive Magistrate on receipt of such information, shall take immediate steps to stop or prevent its occurrence, as the case may be, or pass such order as he deems fit for the protection of such person with disability including an order—

(a) to rescue the victim of such act, authorising the police or any organisation working for persons with disabilities to provide for the safe custody or rehabilitation of such person, or both, as the case may be;

(b) for providing protective custody to the person with disability, if such person so desires;

(c) to provide maintenance to such person with disability.

(4) Any police officer who receives a complaint or otherwise comes to know of abuse, violence or exploitation towards any person with disability shall inform the aggrieved person of—



(a) his or her right to apply for protection under sub-section (2) and the particulars of the Executive Magistrate having jurisdiction to provide assistance;

(b) the particulars of the nearest organisation or institution working for the rehabilitation of persons with disabilities;

(c) the right to free legal aid; and

(d) the right to file a complaint under the provisions of this Act or any other law dealing with such offence:

Provided that nothing in this section shall be construed in any manner as to relieve the police officer from his duty to proceed in accordance with law upon receipt of information as to the commission of a cognizable offence.

(5) If the Executive Magistrate finds that the alleged act or behaviour constitutes an offence under the Indian Penal Code, or under any other law for the time being in force, he may forward the complaint to that effect to the Judicial or Metropolitan Magistrate, as the case may be, having jurisdiction in the matter.

45 of 1860.

Protection and safety.

**8. (1)** The persons with disabilities shall have equal protection and safety in situations of risk, armed conflict, humanitarian emergencies and natural disasters.

(2) The National Disaster Management Authority and the State Disaster Management Authority shall take appropriate measures to ensure inclusion of persons with disabilities in its disaster management activities as defined under clause (e) of section 2 of the Disaster Management Act, 2005 for the safety and protection of persons with disabilities.

53 of 2005.

(3) The District Disaster Management Authority constituted under section 25 of the Disaster Management Act, 2005 shall maintain record of details of persons with disabilities in the district and take suitable measures to inform such persons of any situations of risk so as to enhance disaster preparedness.

53 of 2005.

(4) The authorities engaged in reconstruction activities subsequent to any situation of risk, armed conflict or natural disasters shall undertake such activities, in consultation with the concerned State Commissioner, in accordance with the accessibility requirements of persons with disabilities.

Home and family.

**9. (1)** No child with disability shall be separated from his or her parents on the ground of disability except on an order of competent court, if required, in the best interest of the child.

(2) Where the parents are unable to take care of a child with disability, the competent court shall place such child with his or her near relations, and failing that within the community in a family setting or in exceptional cases in shelter home run by the appropriate Government or non-governmental organisation, as may be required.

Reproductive rights.

**10. (1)** The appropriate Government shall ensure that persons with disabilities have access to appropriate information regarding reproductive and family planning.

(2) No person with disability shall be subject to any medical procedure which leads to infertility without his or her free and informed consent.

Accessibility in voting.

**11.** The Election Commission of India and the State Election Commissions shall ensure that all polling stations are accessible to persons with disabilities and all materials related to the electoral process are easily understandable by and accessible to them.

Access to justice.

**12. (1)** The appropriate Government shall ensure that persons with disabilities are able to exercise the right to access any court, tribunal, authority, commission or any other body having judicial or quasi-judicial or investigative powers without discrimination on the basis of disability.

(2) The appropriate Government shall take steps to put in place suitable support measures for persons with disabilities specially those living outside family and those disabled requiring high support for exercising legal rights.



39 of 1987.

(3) The National Legal Services Authority and the State Legal Services Authorities constituted under the Legal Services Authorities Act, 1987 shall make provisions including reasonable accommodation to ensure that persons with disabilities have access to any scheme, programme, facility or service offered by them equally with others.

(4) The appropriate Government shall take steps to—

(a) ensure that all their public documents are in accessible formats;

(b) ensure that the filing departments, registry or any other office of records are supplied with necessary equipment to enable filing, storing and referring to the documents and evidence in accessible formats; and

(c) make available all necessary facilities and equipment to facilitate recording of testimonies, arguments or opinion given by persons with disabilities in their preferred language and means of communication.

**13.** (1) The appropriate Government shall ensure that the persons with disabilities have right, equally with others, to own or inherit property, movable or immovable, control their financial affairs and have access to bank loans, mortgages and other forms of financial credit.

Legal capacity.

(2) The appropriate Government shall ensure that the persons with disabilities enjoy legal capacity on an equal basis with others in all aspects of life and have the right to equal recognition everywhere as any other person before the law.

(3) When a conflict of interest arises between a person providing support and a person with disability in a particular financial, property or other economic transaction, then such supporting person shall abstain from providing support to the person with disability in that transaction:

Provided that there shall not be a presumption of conflict of interest just on the basis that the supporting person is related to the person with disability by blood, affinity or adoption.

(4) A person with disability may alter, modify or dismantle any support arrangement and seek the support of another:

Provided that such alteration, modification or dismantling shall be prospective in nature and shall not nullify any third party transaction entered into by the person with disability with the aforesaid support arrangement.

(5) Any person providing support to the person with disability shall not exercise undue influence and shall respect his or her autonomy, dignity and privacy.

**14.** (1) Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, on and from the date of commencement of this Act, where a district court or any designated authority, as notified by the State Government, finds that a person with disability, who had been provided adequate and appropriate support but is unable to take legally binding decisions, may be provided further support of a limited guardian to take legally binding decisions on his behalf in consultation with such person, in such manner, as may be prescribed by the State Government:

Provision for guardianship.

Provided that the District Court or the designated authority, as the case may be, may grant total support to the person with disability requiring such support or where the limited guardianship is to be granted repeatedly, in which case, the decision regarding the support to be provided shall be reviewed by the Court or the designated authority, as the case may be, to determine the nature and manner of support to be provided.

*Explanation.*—For the purposes of this sub-section, “limited guardianship” means a system of joint decision which operates on mutual understanding and trust between the guardian and the person with disability, which shall be limited to a specific period and for specific decision and situation and shall operate in accordance to the will of the person with disability.



(2) On and from the date of commencement of this Act, every guardian appointed under any provision of any other law for the time being in force, for a person with disability shall be deemed to function as a limited guardian.

(3) Any person with disability aggrieved by the decision of the designated authority appointing a legal guardian may prefer an appeal to such appellate authority, as may be notified by the State Government for the purpose.

Designation of authorities to support.

**15.** (1) The appropriate Government shall designate one or more authorities to mobilise the community and create social awareness to support persons with disabilities in exercise of their legal capacity.

(2) The authority designated under sub-section (1) shall take measures for setting up suitable support arrangements to exercise legal capacity by persons with disabilities living in institutions and those with high support needs and any other measures as may be required.

### CHAPTER III

#### EDUCATION

Duty of educational institutions.

**16.** The appropriate Government and the local authorities shall endeavour that all educational institutions funded or recognised by them provide inclusive education to the children with disabilities and towards that end shall—

(i) admit them without discrimination and provide education and opportunities for sports and recreation activities equally with others;

(ii) make building, campus and various facilities accessible;

(iii) provide reasonable accommodation according to the individual's requirements;

(iv) provide necessary support individualised or otherwise in environments that maximise academic and social development consistent with the goal of full inclusion;

(v) ensure that the education to persons who are blind or deaf or both is imparted in the most appropriate languages and modes and means of communication;

(vi) detect specific learning disabilities in children at the earliest and take suitable pedagogical and other measures to overcome them;

(vii) monitor participation, progress in terms of attainment levels and completion of education in respect of every student with disability;

(viii) provide transportation facilities to the children with disabilities and also the attendant of the children with disabilities having high support needs.

Specific measures to promote and facilitate inclusive education.

**17.** The appropriate Government and the local authorities shall take the following measures for the purpose of section 16, namely:—

(a) to conduct survey of school going children in every five years for identifying children with disabilities, ascertaining their special needs and the extent to which these are being met:

Provided that the first survey shall be conducted within a period of two years from the date of commencement of this Act;

(b) to establish adequate number of teacher training institutions;

(c) to train and employ teachers, including teachers with disability who are qualified in sign language and Braille and also teachers who are trained in teaching children with intellectual disability;

(d) to train professionals and staff to support inclusive education at all levels of school education;





(e) to establish adequate number of resource centres to support educational institutions at all levels of school education;

(f) to promote the use of appropriate augmentative and alternative modes including means and formats of communication, Braille and sign language to supplement the use of one's own speech to fulfill the daily communication needs of persons with speech, communication or language disabilities and enables them to participate and contribute to their community and society;

(g) to provide books, other learning materials and appropriate assistive devices to students with benchmark disabilities free of cost up to the age of eighteen years;

(h) to provide scholarships in appropriate cases to students with benchmark disability;

(i) to make suitable modifications in the curriculum and examination system to meet the needs of students with disabilities such as extra time for completion of examination paper, facility of scribe or amanuensis, exemption from second and third language courses;

(j) to promote research to improve learning; and

(k) any other measures, as may be required.

**18.** The appropriate Government and the local authorities shall take measures to promote, protect and ensure participation of persons with disabilities in adult education and continuing education programmes equally with others.

Adult  
education.

#### CHAPTER IV

##### SKILL DEVELOPMENT AND EMPLOYMENT

**19.** (1) The appropriate Government shall formulate schemes and programmes including provision of loans at concessional rates to facilitate and support employment of persons with disabilities especially for their vocational training and self-employment.

Vocational  
training and  
self-  
employment.

(2) The schemes and programmes referred to in sub-section (1) shall provide for—

(a) inclusion of person with disability in all mainstream formal and non-formal vocational and skill training schemes and programmes;

(b) to ensure that a person with disability has adequate support and facilities to avail specific training;

(c) exclusive skill training programmes for persons with disabilities with active links with the market, for those with developmental, intellectual, multiple disabilities and autism;

(d) loans at concessional rates including that of microcredit;

(e) marketing the products made by persons with disabilities; and

(f) maintenance of disaggregated data on the progress made in the skill training and self-employment, including persons with disabilities.

**20.** (1) No Government establishment shall discriminate against any person with disability in any matter relating to employment:

Non-  
discrimination  
in  
employment.

Provided that the appropriate Government may, having regard to the type of work carried on in any establishment, by notification and subject to such conditions, if any, exempt any establishment from the provisions of this section.

(2) Every Government establishment shall provide reasonable accommodation and appropriate barrier free and conducive environment to employees with disability.

(3) No promotion shall be denied to a person merely on the ground of disability.

(4) No Government establishment shall dispense with or reduce in rank, an employee who acquires a disability during his or her service:



Provided that, if an employee after acquiring disability is not suitable for the post he was holding, shall be shifted to some other post with the same pay scale and service benefits:

Provided further that if it is not possible to adjust the employee against any post, he may be kept on a supernumerary post until a suitable post is available or he attains the age of superannuation, whichever is earlier.

(5) The appropriate Government may frame policies for posting and transfer of employees with disabilities.

Equal opportunity policy.

**21.** (1) Every establishment shall notify equal opportunity policy detailing measures proposed to be taken by it in pursuance of the provisions of this Chapter in the manner as may be prescribed by the Central Government.

(2) Every establishment shall register a copy of the said policy with the Chief Commissioner or the State Commissioner, as the case may be.

Maintenance of records.

**22.** (1) Every establishment shall maintain records of the persons with disabilities in relation to the matter of employment, facilities provided and other necessary information in compliance with the provisions of this Chapter in such form and manner as may be prescribed by the Central Government.

(2) Every employment exchange shall maintain records of persons with disabilities seeking employment.

(3) The records maintained under sub-section (1) shall be open to inspection at all reasonable hours by such persons as may be authorised in their behalf by the appropriate Government.

Appointment of Grievance Redressal Officer.

**23.** (1) Every Government establishment shall appoint a Grievance Redressal Officer for the purpose of section 19 and shall inform the Chief Commissioner or the State Commissioner, as the case may be, about the appointment of such officer.

(2) Any person aggrieved with the non-compliance of the provisions of section 20, may file a complaint with the Grievance Redressal Officer, who shall investigate it and shall take up the matter with the establishment for corrective action.

(3) The Grievance Redressal Officer shall maintain a register of complaints in the manner as may be prescribed by the Central Government, and every complaint shall be inquired within two weeks of its registration.

(4) If the aggrieved person is not satisfied with the action taken on his or her complaint, he or she may approach the District-Level Committee on disability.

## CHAPTER V

### SOCIAL SECURITY, HEALTH, REHABILITATION AND RECREATION

Social security.

**24.** (1) The appropriate Government shall within the limit of its economic capacity and development formulate necessary schemes and programmes to safeguard and promote the right of persons with disabilities for adequate standard of living to enable them to live independently or in the community:

Provided that the quantum of assistance to the persons with disabilities under such schemes and programmes shall be at least twenty-five per cent. higher than the similar schemes applicable to others.

(2) The appropriate Government while devising these schemes and programmes shall give due consideration to the diversity of disability, gender, age, and socio-economic status.

(3) The schemes under sub-section (1) shall provide for,—

(a) community centres with good living conditions in terms of safety, sanitation, health care and counselling;

(b) facilities for persons including children with disabilities who have no family or have been abandoned, or are without shelter or livelihood;

(c) support during natural or man-made disasters and in areas of conflict;



(d) support to women with disability for livelihood and for upbringing of their children;

(e) access to safe drinking water and appropriate and accessible sanitation facilities especially in urban slums and rural areas;

(f) provisions of aids and appliances, medicine and diagnostic services and corrective surgery free of cost to persons with disabilities with such income ceiling as may be notified;

(g) disability pension to persons with disabilities subject to such income ceiling as may be notified;

(h) unemployment allowance to persons with disabilities registered with Special Employment Exchange for more than two years and who could not be placed in any gainful occupation;

(i) care-giver allowance to persons with disabilities with high support needs;

(j) comprehensive insurance scheme for persons with disability, not covered under the Employees State Insurance Schemes, or any other statutory or Government-sponsored insurance schemes;

(k) any other matter which the appropriate Government may think fit.

25. (1) The appropriate Government and the local authorities shall take necessary measures for the persons with disabilities to provide,— Healthcare.

(a) free healthcare in the vicinity specially in rural area subject to such family income as may be notified;

(b) barrier-free access in all parts of Government and private hospitals and other healthcare institutions and centres;

(c) priority in attendance and treatment.

(2) The appropriate Government and the local authorities shall take measures and make schemes or programmes to promote healthcare and prevent the occurrence of disabilities and for the said purpose shall—

(a) undertake or cause to be undertaken surveys, investigations and research concerning the cause of occurrence of disabilities;

(b) promote various methods for preventing disabilities;

(c) screen all the children at least once in a year for the purpose of identifying “at-risk” cases;

(d) provide facilities for training to the staff at the primary health centres;

(e) sponsor or cause to be sponsored awareness campaigns and disseminate or cause to be disseminated information for general hygiene, health and sanitation;

(f) take measures for pre-natal, perinatal and post-natal care of mother and child;

(g) educate the public through the pre-schools, schools, primary health centres, village level workers and *anganwadi* workers;

(h) create awareness amongst the masses through television, radio and other mass media on the causes of disabilities and the preventive measures to be adopted;

(i) healthcare during the time of natural disasters and other situations of risk;

(j) essential medical facilities for life saving emergency treatment and procedures; and

(k) sexual and reproductive healthcare especially for women with disability.

26. The appropriate Government shall, by notification, make insurance schemes for their employees with disabilities. Insurance schemes.

27. (1) The appropriate Government and the local authorities shall within their economic capacity and development, undertake or cause to be undertaken services and programmes of Rehabilitation.